Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LII (52), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

दक्षिण एशिया की समकालिक राजनीति में उभरते Gen Z आंदोलन: एक विस्तृत सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषण

दीपिका शर्मा *

* शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना – Gen Z आंदोलन आखिर है क्या... और समकालिक राजनीति में ये इतने प्रभावशाली कैसे होने लगे हैं? अगर इस प्रश्न की गहराई में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि 1997 से 2012 के मध्य जन्मी पीढ़ी 'Gen Z' कहलाती है, और यह केवल सांख्यिकीय आंकड़ा न होकर डिजिटल युग की पहली पीढ़ी है, जो अपरंपरागत तरीके अर्थात् सोशल मीडिया के माध्यम से परस्पर संगठित होकर किसी राजनीतिक या सामाजिक विषय हेतु एक आभासी (Virtual) मंच पर, एक स्वर में, अपनी आवाज को जन-जन तक पहुँचाती है। ये शिक्षा व्यवस्था में आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सुधार, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, लोकतांत्रिक अधिकारों तथा मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, साथ ही महँगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, कुशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते दिखाई देते हैं। परंतु समय के साथ इनकी भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन आया हैय इन्होंने 'वर्चुअल' आवाज को 'वास्तविक' आंदोलन में बदला है।

दक्षिण एशियाई देशों को 'अपरिपक्व राजनीतिक संस्कृति' के अंतर्गत रखा गया है, जहाँ पारंपरिक आंदोलन अक्सर धर्म, जाति और क्षेत्रीयता जैसे संकीर्ण मुद्दों से प्रभावित होते रहे हैं। परंतु Gen Z आंदोलनों ने इन्हें एक नई दिशा दी है। परंपरागत स्वरूप से भिन्न, ये आंदोलन न तो दलगत राजनीति के कुचक्र में निर्मित होते हैं, न ही सत्ता के रूढ़िवादी स्वर को मुखरित करते हैं।

वैसे इनका स्वरूप हर देश में अलग-अलग होता है, जो वहाँ फैली अव्यवस्था, लोगों की जागृत चेतना, जनसंचार के साधनों (Social Media) के विस्तार और उस व्यवस्था के खिलाफ 'संगठित नेतृत्व' जैसे तत्वों से मिलकर निर्धारित होता है। कभी-कभी यह आंदोलन शांति और अहिंसा के माध्यम से, जनसंचार की नई-नई तकनीकों से जनमानस में अपनी पैठ बनाते हैं, तो कभी-कभी अपने उग्र रूप में सशस्त्र हो, सत्ता का तख्ता पलट करने में भी नहीं चूकते। मानो अपने अंदर समाहित विद्रोह का ज्वालामुखी एक छिद्र के माध्यम से सब कुछ तहस-नहस कर देता है, इनका तात्कालिक स्वरूप भी कुछ ऐसा ही रहा है।

बांग्लादेश में सुधार से क्रांति और उसके बाद की चुनौती को देखा जाए, तो हम पाते हैं कि 2018 में बांग्लादेश में हुआ सड़क सुरक्षा आंदोलन Gen Z की क्षमता का प्रथम परिचायक था। यह आंदोलन भ्रष्ट ट्रैफिक सिस्टम एवं राजनेताओं की बदौलत बिना लाइसेंस के ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली बसों से छात्रों की मृत्यु पर, क्रोधित छात्रों के नेतृत्व में उभरा। इसमें न केवल रिश्वतखोरी का सार्वजनिक पर्दाफाश किया गया, बल्कि छात्रों द्वारा ट्रैफिक नियंत्रण को भी अपने हाथ में लेकर, भली-भांति संभाला गया। इस आंदोलन द्वारा यह सिद्ध किया गया कि Gen Z केवल विरोध ही नहीं, बल्कि 'शासन (Governance)' भी कर सकती है।

बांग्लादेश में हुआ कोटा सुधार आंदोलन (2024) और सत्ता का परिवर्तन भी इसी श्रेणी में आता है। स्वतंत्रता सेनानियों, महिलाओं एवं जिला कोटा के नाम पर सरकारी नौकरियों में लगभग 56% आरक्षण की पृष्ठभूमि पर खड़ा हुआ यह आंदोलन, जिसे युवाओं ने 'निहायत अन्यायपूर्ण एवं प्रतिस्पर्धा-विरोधी' बताया, एक ऐतिहासिक क्रांति में बदल गया। इसकी जड़ें राजनीतिक केंद्रीकरण, एक-दलीय प्रभुत्व और संस्थागत क्षरण में थीं। सरकारी दमन, प्रतिबंध और हजारों की गिरफ्तारियों ने इस चिंगारी को एक दावानल में बदल दिया।

वह आंदोलन, जो सीमित मांग एवं 'कोटा बनाम मेरिट' के संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था, ने राज्य के कठोर दमन के पश्चात 'राज्य बनाम नागरिक' की बहस का रूप ले लिया। सोशल मीडिया एक 'वैकल्पिक सार्वजनिक मंच बनकर उभरा, जिस पर दमन के चलचित्रों को साझा कर जनमत को एकजुट किया गया। अंततः, अगस्त 2024 में शेख हसीना का पद छोड़ना एक युग के अंत की घटना सिद्ध हुई।

किंतु 2025 में आए क्रांति के बाद के संकट को दरकिनार नहीं किया जा सकता। हालाँकि नवीन गठित अंतरिम सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा की गई, किंतु 2025 में एक प्रमुख छात्र नेता की हत्या ने विरोध को पुनः जीवित कर दिया। इसने छात्रों की उग्र भावुकता और राजनीतिक स्पष्टता के बीच के तनाव को गहरा किया। इससे यह प्रतीत होता है कि वे आंदोलन की उग्रता से सत्ता को चुनौती देने में तो सक्षम हैं, किंतु उसके बाद की राजनीति को संभालना और उसमें स्थिरता लाना उनके लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

2022 में श्रीलंका का 'अरागलाया' (Aragalaya) आंदोलन और सांस्कृतिक प्रतिरोध, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और संस्थागत क्षरण के परिणामस्वरूप छाई महामंदी और आर्थिक संकट से पनपा था। जब आम आदमी को मूलभूत आवश्यकताओं- ईंधन, भोजन और दवाइयों की भारी कमी से जूझना पड़ा, तो इस जन-आंदोलन ने जन्म लिया। यह आंदोलन किसी विचारधारा या पार्टी के झंडे के तले नहीं लड़ा गया, बल्कि यह विरोध ळमर्द द्वारा सांस्कृतिक कलाओं, रचनात्मकता, नुक्कड़ नाटकों और सामूहिक

बहसों के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसकी चरम परिणति राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के रूप में दिखाई दी। इसने सिद्ध किया कि युवाओं की रचनात्मकता बंदूकों से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है।

विशेष तौर पर यदि नेपाल की समकालिक राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाए, तो हम पाते हैं कि नेपाल का Gen Z आंदोलन स्वरूप में अत्यधिक 'डिजिटल-केंद्रित' है, लेकिन इसकी जड़ें गहरी संरचनात्मक समस्याओं में हैं। यहाँ आंदोलनों का मूल कारण लंबी राजनीतिक अस्थिरता, गठबंधन की राजनीति, कुशासन, पुराने दलों (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) द्वारा सत्ता का एकाधिकार, और शिक्षा-स्वास्थ्य की बदहाली रही है।

तात्कालिक कारण बना 2020 के दौरान कोविड-19 से जूझने की सरकारी विफलता। इसने युवाओं को सिद्ध कर दिया कि 'नेपाल में राजतंत्र तो गया है, लेकिन सत्ता की संस्कृति नहीं बदली है।' इसी वजह से युवाओं ने 'इनफ इज इनफ' अभियान के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से एकजुट होकर सड़क पर उतरकर 'बिना पार्टी, बिना नेता, बिना झंडा' की रणनीति के साथ सत्याग्रह किया। यह नेपाल में Gen Z की राजनीतिक सक्रियता की पहली बड़ी पहचान बना।

2021 में 'नो मोर करप्शन' और 'वी नीड अकाउंटेबिलिटी' जैसे नारों के साथ युवा प्रोफेशनल्स सड़कों पर उतरे। इसके परिणाम 2022 के चुनावों में दिखाई पड़े। काठमांडू के मेयर चुनाव में एक स्वतंत्र युवा उम्मीदवार (बालेन शाह) को Gen Z का जबरदस्त समर्थन मिला। यह पारंपरिक दलों के खिलाफ एक 'एंटी-एस्टेब्लिशमेंट वोट' था। युवाओं ने साबित किया कि वे चाहें तो चुनावी राजनीति को पलटकर रख सकते हैं।

और सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का सबसे नया अध्याय 2025 में लिखा गया, जब सरकार ने टिक-टॉक (Tik Tok) और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया। यह कदम युवाओं को सिर्फ सेंसरशिप नहीं, बल्कि उनके निजी जीवन और अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला लगा।

प्रतिक्रिया के रूप में इसके विरोध की शुरुआत सड़क से लेकर संसद तक 'डिजिटल अधिकारों' से हुई, लेकिन जल्द ही यह भ्रष्टाचार, राजनीतिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यापक बहस में बदल गया। नेपाल के Gen Z आंदोलन के स्वरूप की सबसे खास बात यह रही कि इसमें शहरों और कस्बों के युवा समान रूप से शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने 'इंटरनेट तक पहुँच' के सवाल को 'लोकतंत्र की गुणवत्ता' के साथ सीधा जोड़ दिया।

इस पर राज्य की दमनकारी पुलिस कार्रवाई और हिंसा ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया, जिससे आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला। अंततः सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़े और नेतृत्व में भी बदलाव हुआ। यह संकेत देता है कि अब Gen Z की नाराजगी को नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है।

नेपाल के अनुभव ने यह दिखाया कि भविष्य की राजनीति में 'डिजिटल स्वतंत्रता' केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि राजनीतिक स्थिरता की शर्त है। नेपाल का ळमर्द केवल सत्ता-विरोधी नहीं है, बल्कि वे एक 'नए लोकतांत्रिक अनुबंध' (New Democtaric Contract) की मांग कर रहे हैं जिसमें राज्य नागरिकों पर भरोसा करे, न कि उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करे।

दक्षिण एशियाई देशों में इन तीनों देशों (बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल) में हुए आंदोलनों के विस्तृत अनुभव यह बताते हैं कि Gen Z आंदोलन का उदय कोई क्षणिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक चेतना में होने वाले व्यापक बदलाव का संकेत है। यह पीढ़ी न केवल आर्थिक सुधार चाहती है, बल्कि सत्ता और नागरिक के मध्य संबंधों को 'पुनः परिभाषित' भी करना चाहती है। हालाँकि ये आंदोलन सरकारों को गिराने की हद तक सफल हुए हैं, लेकिन उनके सम्मुख जो सबसे कठिन चुनौती है, वह है 'स्थायी, लोकतांत्रिक एवं समावेशी संस्थाओं का निर्माण', क्योंकि 'सड़क' पर जीतना तो आसान माना जाता है, लेकिन 'सदन' को चलाना कठिन। यदि Gen Z इस 'निर्माण' की चुनौती का सामना कर पाते हैं, तो वे दक्षिण एशिया की राजनीति को आने वाले दशकों में पूरी तरह बदलने का सामर्थ्य रखते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Scroll.in, 2025. *Youth-led protests and democratic challenges in contemporary South Asia*. Scroll.in, New Delhi.
2. The Hindu, 2025. *The rise of Gen Z movements and changing patterns of political mobilisation in South Asia.* The Hindu, Chennai.
3. Al Jazeera, 2025. *South Asia's youth revolts: Bangladesh, Sri Lanka and Nepal in comparative perspective*. Al Jazeera.
4. Himal Southasian, 2025. *Popular uprisings, economic crisis and youth resistance in South Asia*. Himal Southasian.
5. Encyclopaedia Britannica, 2025. *Youth protest movements and political change in South Asia*. Encyclopaedia Britannica.
6. Economic and Political Weekly (EPW), various issues. *Commentaries on digital activism, youth politics and democratic instability in South Asia*. EPW, Mumbai.
7. United Nations Development Programme (UNDP), 2023–24. *Youth, digital participation and democratic governance in South Asia*. UNDP Reports.

****